



## संघर्ष में एक अहम पड़ाव

वैसे तो भांति-भांति के विषाणुओं और जीवाणुओं पर काम करने वाले कई टीके पहले से मौजूद हैं, लेकिन यह पहला मौका है जब डब्ल्यूएचओ ने ह्यूमन पैरासाइट के खिलाफ किसी टीके के व्यापक उपयोग की सिफारिश की है।

आरती सिंह।।

बीमारियों के खिलाफ चलने वाले मनुष्यता के सतत संघर्ष में एक अहम पड़ाव तब आया, जब डब्ल्यूएचओ ने मलेरिया के टीके आरटीएसएस को अपनी मान्यता दे दी। वैसे तो भांति-भांति के विषाणुओं और जीवाणुओं पर काम करने वाले कई टीके पहले से मौजूद हैं, लेकिन यह पहला मौका है जब डब्ल्यूएचओ ने ह्यूमन पैरासाइट के खिलाफ किसी टीके के व्यापक उपयोग की सिफारिश की है। इसकी वैज्ञानिक अहमियत इस बात से समझी जा सकती है कि रिसर्चर्स पिछले सौ साल से इस बीमारी का प्रभावी टीका बनाने की कोशिश में लगे थे।

मलेरिया से हमारा वास्ता लंबे समय से पड़ता रहा है और तमाम उपायों की

बदौलत आज भले यह अपने खौफनाक रूप में नजर न आता हो, लेकिन एक समय था, खासकर 50 का दशक जब भारत में भी सालाना मलेरिया के सात करोड़ से ज्यादा मामले सामने आते थे और आठ लाख तक मौतें दर्ज की जाती थीं। अब भारत में उतना बुरा हाल नहीं है लेकिन दुनिया भर में अब भी इससे हर साल करीब चार लाख मौतें होती हैं। इसका सबसे ज्यादा प्रभाव अफ्रीकी देशों में है। वहां पांच साल से कम उम्र के बच्चे इसका सबसे ज्यादा शिकार बनते हैं।

हालांकि इससे बचाव के उपाय भी कम नहीं किए जाते। 2019 में ही मलेरिया नियंत्रण व उन्मूलन पर तीन अरब डॉलर खर्च किए गए। मगर इसके बावजूद इन देशों में मलेरिया का आतंक कायम है। निश्चित रूप से उन इलाकों के लोगों के लिए यह टीका वरदान बनकर आया है। फिर भी सारी उम्मीदें इसी पर टिका देना समझदारी नहीं होगी। वैसे पायलट प्रोग्राम के दौरान इसके नतीजे उत्साहवर्धक रहे हैं, लेकिन फिर भी इसकी अपनी सीमाएं हैं। पहली बात तो यह समझने की है कि मलेरिया पैरासाइट के सौ से अधिक प्रकार हैं। आरटीएसएस टीका इनमें से एक प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम पर ही कारगर है, हालांकि यही सबसे खतरनाक माना जाता है और अफ्रीकी देशों में सबसे ज्यादा प्रकोप भी इसी का होता है। दूसरी बात यह कि इस वैक्सीन के प्रभावी होने के लिए हर बच्चे को इसका



चार डोज देना जरूरी होगा।

इनमें से पहले तीन डोज क्रमशः पांच, छह और सात महीने की उम्र में तो चौथा डोज 18वें महीने में देने की जरूरत होगी। दूरदराज के इलाकों में बच्चों को समय से चारों डोज लगाना व्यवहार में आसान नहीं होगा। वैसे, अच्छी योजना बनाकर इस मुश्किल का हल निकाला जा सकता है। मलेरिया की नई दवाओं को लेकर भी हाल कोई अच्छा नहीं रहा। इस तरह के आरोप लगे कि दवा कंपनियों को खासतौर पर गरीब मुल्कों की इस बीमारी में बड़ा मुनाफा नहीं दिखा, इसलिए उन्होंने मलेरिया की नई दवाएं नहीं बनाईं। जिस तरह से बच्चों की खातिर यह टीका आया है, कुछ वैसी ही पहल इस बीमारी की नई दवा बनाने को लेकर भी होना चाहिए।

## उपदेश

अशोक वोहरा।

“हां बापू, समझ गया।” एक दिन लड़के ने सोचा, क्यों न आज राजा के घर पर ही हाथ साफ कर दूं। ऐसा सोचकर उधर ही चल पड़ा। थोड़ी दूर जाने के बाद

धर्म-दर्शन



उसने देखा कि रास्ते में बगल में कुछ लोग एकत्र होकर खड़े हैं। उसने एक आते हुए व्यक्ति से पूछा, “उस स्थान पर इतने लोग क्यों एकत्र हुए हैं? उस आदमी ने उत्तर दिया, “वहां एक महात्मा उपदेश दे रहे हैं।” यह सुनकर उसका माथा ठनका। “इसका उपदेश नहीं सुनूंगा।” ऐसा सोचकर अपने कानों में उंगली डालकर वह वहां से भाग निकला। जैसे ही वह भीड़ के निकट पहुंचा एक पत्थर से टोकर लगी और वह गिर गया। उस समय महात्मा जी कह रहे थे, “कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। जिसका नामक खाएं उसका कभी बुरा नहीं सोचना चाहिए। ऐसा करने वाले को भगवान सदा सुखी बनाए रखते हैं।”

## संपादकीय

### कोयले से तौबा

मूल बात यह समझने की है कि दुनिया का कोई भी देश कोयला और जैव ईंधन का इस्तेमाल जारी रखते हुए वायु प्रदूषण का स्तर कम करने में कामयाब नहीं हुआ है। यूरोप और अमेरिका में कोयला और जैव ईंधन ऊर्जा के बड़े स्रोत नहीं हैं। चीन भी अगर पेइचिंग में वायु प्रदूषण का स्तर कम कर सका तो यह पावर प्लांट्स और इंडस्ट्रीज में कोयले की खपत घटाकर और लाखों घरों तक साफ कुकिंग फ्यूल पहुंचाकर ही संभव हुआ। अफसोस की बात है कि आज भी दिल्ली सरकार का, बल्कि कहे पूरे देश का एक्शन प्लान ऑटोमोबाइल सेक्टर पर जरूरत से ज्यादा केंद्रित है। दूसरे शब्दों में, यह पलूशन की समस्या के 15 फीसदी हिस्से को ही संबोधित कर रहा है। बाकी 85 फीसदी यानी जैव ईंधन, कोयला और भूमि प्रबंधन से जुड़े पहलू काफी जटिल हैं और ऊर्जा तथा भूमि प्रबंधन नीतियों में आधारभूत बदलाव की मांग करते हैं। इनके लिए कड़े फैसलों की जरूरत है, जिससे तमाम राजनीतिज्ञ बचना चाहते हैं। आखिर, स्मॉग टावर लगाकर अपने वोटों को यह अहसास दिलाना आसान होता है कि सरकार एयर पलूशन को कंट्रोल करने का प्रयास कर रही है बजाय इसके कि चुनावी वर्ष में पंजाब में किसानों को पराली जलाने से सचमुच रोका जाए। हमें भी यही रास्ता अपनाना होगा। इसलिए अगर कोई पार्टी या नेता आपको यह सपना दिखाए कि कुछ वर्षों के अंदर वायु प्रदूषण दूर हो जाएगा तो यकीन न करें। कम से कम एक दशक के कठिन संक्रमण काल से गुजरने के बाद ही हम साफ हवा में सांस ले सकेंगे।

न्यायपालिका भी पीछे नहीं दिखना चाहती। सो, नैशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की ओर से सुओमोटो निर्देश आने लगते हैं। यह सब मार्च तक चलता है और फिर सब कुछ सामान्य हो जाता है।

## बाहर से आता प्रदूषण

चंद्रभूषण।।

एक रिवाज सा बन गया है। अक्टूबर-नवंबर में जैसे ही दिल्ली की हवा की क्वालिटी खराब और गंभीर की श्रेणी में आती है, परस्पर दोषारोपण का खेल शुरू हो जाता है। सड़कों पर पानी का छिड़काव, ऑड-ईवन के नियम और स्मॉग टावर जैसी कवायदें दिखने लगती हैं ताकि लोगों को ऐसा लगे कि पलूशन कम करने के इंतजाम किए जा रहे हैं। न्यायपालिका भी पीछे नहीं दिखना चाहती। सो, नैशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की ओर से सुओमोटो निर्देश आने लगते हैं। यह सब मार्च तक चलता है और फिर सब कुछ सामान्य हो जाता है, अगले अक्टूबर-नवंबर तक के लिए।

सवाल यह है कि आखिर गड़बड़ी कहाँ हो रही है? हम दिल्ली में प्रदूषण कम करने में कामयाब क्यों नहीं हो पा रहे? तमाम प्रदूषणकारी उद्योग दिल्ली के बाहरी इलाकों में शिफ्ट किए जा चुके हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सीएनजी पर जा चुका है, पावर प्लांट्स बंद हो चुके हैं, वाहनों से उत्सर्जन के कड़े कानून लागू हैं, भारी वाहनों के प्रवेश पर पाबंदियां हैं, जेनरेटर सेट भी सीमित हैं। इन सबके बावजूद दिल्ली में पीएम 2.5 लेवल पिछले दशक में दोगुने से भी ज्यादा हो गया है। आखिर क्यों?

इस सवाल का जवाब पाने के लिए हमें समस्या



की प्रकृति को समझना होगा और फिर देखना होगा कि जो उपाय किए जा रहे हैं, वे उपयुक्त हैं या नहीं। पहली बात तो यह ध्यान में रखने की है कि दिल्ली का भूभाग एनसीआर (नैशनल कैपिटल रीजन) का महज 2.7 फीसदी है। यानी दिल्ली का वायु प्रदूषण सिर्फ इसके अपने स्रोतों की वजह से नहीं है। हालांकि प्रदूषण का कितना हिस्सा बाहर से आता है, इस बारे में अलग-अलग अनुमान हैं (कुछ अनुमानों के मुताबिक तो यह हिस्सा 60 फीसदी तक है), लेकिन इतना तय है कि हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में प्रदूषण को नियंत्रित किए बगैर दिल्ली की हवा की क्वालिटी में उल्लेखनीय सुधार नहीं किया जा सकता। दूसरी बात यह कि प्रदूषण का सीधा रिश्ता इस बात

से है कि हम क्या जलाते हैं। साल 2019 में देश में ऊर्जा संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए 183 करोड़ टन जीवाश्म ईंधन और जैव ईंधन जलाए गए। इसके अलावा करीब 10 करोड़ टन खेती के अवशेष और एक से डेढ़ करोड़ टन कचरा खुले में जलाया गया। कुल मिलाकर, हमने उस साल कम से कम 195 करोड़ टन सामग्री जलाई जिसका 85 फीसदी हिस्सा कोयला और जैव ईंधन था। पेट्रोलियम पदार्थ 15 फीसदी से भी कम थे। अगर हम जलाई गई इन चीजों का हिसाब लगाएं तो राष्ट्रीय स्तर पर कम से कम 85 फीसदी वायु प्रदूषण कोयला, जैव ईंधन और कचरे से पैदा हो रहा है। पेट्रोलियम पदार्थों और गैस का योगदान 15 फीसदी से भी कम है।

तीसरा, डस्ट पार्टिक्युलेट मैटर (पीएम) पलूशन के एक बड़े स्रोत के रूप में उभरा है। अध्ययन बताते हैं कि दिल्ली में पीएम 2.5 का 20 से 30 फीसदी तक हिस्सा कंस्ट्रक्शन साइटों, सड़कों के किनारों और आसपास के राज्यों से हवा में उड़कर आने वाली धूलों की उपज होता है। दरअसल, भूक्षरण और मरुस्थलीकरण अब पूरे देश में धूल प्रदूषण का बड़ा स्रोत बन गया है। देश की कुल जमीन का करीब 30 फीसदी या तो अवक्रमित हो चुका है या मरुस्थलीकरण से गुजर रहा है।

सूचीक बवाल- 5351	****	अनिता
2		4
6		1
5	8	2 3
7		6
3		8
1 6	3	7
2		5
8		4

सूचीक कसबत- 5350 कस तल

6 5 4 3 1 9 7 2 8
7 2 3 5 8 4 9 6 1
8 9 1 7 2 6 3 4 5
1 7 2 8 3 2 5 9 4
4 3 8 9 6 5 1 7 6
5 6 9 4 7 1 8 3 2
2 8 7 1 4 3 6 5 9
9 1 6 2 5 7 4 8 3
3 4 5 6 9 8 2 1 7

■ प्रत्येक संकेत में 7 से 9 तक के अंक भरने वाले आकारक हैं।  
■ प्रत्येक अंक और छोटी संकेत में एवं 3x3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें।  
■ स्थानों से मौजूद अंकों को आप हटा सकते हैं।  
■ खोली का केवल एक ही हल है।

### अपना ब्लॉग

भूमि मरुस्थलीकरण रोकने पर होना चाहिए फोकस

मोहन। स्पष्ट है कि अगर हम दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर कम करना चाहते हैं तो हमारा फोकस कोयला, जैव ईंधन और पराली जलाना कम करने पर, दिल्ली-एनसीआर और आसपास के राज्यों में भूमि मरुस्थलीकरण रोकने पर होना चाहिए। दुर्भाग्यवश, पिछले बीस वर्षों से हम उलटा ही कर रहे हैं। वायु प्रदूषण कम करने संबंधी हमारे तमाम प्रयासों के केंद्र में ऑटोमोबाइल सेक्टर है, जिसमें ज्यादातर पेट्रोलियम उत्पाद ही इस्तेमाल होते हैं। पावर प्लांट्स, इंडस्ट्रीज, जैव ईंधन इस्तेमाल और भूमि प्रबंधन आदि पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा सका। यही वजह है कि हमारे तमाम प्रयासों के बावजूद दिल्ली का वायु प्रदूषण स्तर घटने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन अगर हम वायु प्रदूषण की मात्रा में सचमुच कमी लाना चाहते हैं तो हमारे सामने कोई आसान रास्ता नहीं है। हमें लाखों घरों तक पहुंच कर जैव ईंधन का रसोई में इस्तेमाल रोकना होगा, लाखों किसानों तक पहुंचकर उन्हें पराली न जलाने के लिए मनाना होगा, उनकी जमीन बचाने का इंतजाम करना होगा और हजारों इंडस्ट्रीज में कोयले से होने वाला प्रदूषण कम करने की व्यवस्था करनी होगी।

